News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

यमुना में गंदा पानी गिरने से रोकेंगे वेट लैंड्स

■ मनीष अग्रवाल, नई दिल्ली

यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नालों में से एक बारापुला ड्रेन के पानी को साफ करने की डीडीए ने एक अहम योजना तैयार की है। इसके तहत इस नाले के यमुना में गिरने वाले लास्ट पॉइंट से पहले इसके पानी को वेट लैंड के जरिए ट्रीट किया जाएगा। फिर साफ पानी को यमुना में गिराया जाएगा। इसे बायलॉजिकल मेथड से साफ किया जाएगा। साथ ही यहां ओखला बर्ड सेंक्चुरी के पास बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाया जाएगा। इस बारे में डीडीए ने लैंड्स डिपार्टमेंट को यमुना किनारे हो रही खेती और रह रहे लोगों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश भी दिए हैं।

डीडीए के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए गुरुवार को अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बलविंदर कुमार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सी. आर. बाबू सहित अन्य अधिकारियों ने यमुना नदी के किनारे इस एरिया की विजिट की थी। इसके बाद प्लान तैयार किया गया है कि यमुना नदी किनारे ओखला बर्ड सेंक्चुरी के करीब बारापुला नाले के गंदे पानी को साफ करने के लिए वेट लैंड्स डिवेलप किए जाएंगे। इसके तहत नाले के पानी को यमुना में गिरने से पहले उसे कई तालाबों में से होकर गुजारा जाएगा।

हरेक वेट लैंड में जैविक पद्धति से पानी को साफ किया जाएगा। अंत में जब पानी इतना साफ हो जाएगा कि उसके यमुना में गिरने से नदी में पॉल्यूशन न हो, तब इस पानी को यमुना में बहाया जाएगा। भविष्य में इस तरह की संभावनाएं अन्य नालों के लिए भी खोजी जाएंगी। इससे यमुना में एक बार फिर से पानी में रहने वाले जीव-जंतुओं को जीवन मिलना शुरू हो जाएगा।

बंद हुआ राजघाट प्लांट

प्रस, नई दिल्ली : दिल्ली का सबसे ओल्ड पावर प्लांट, राजघाट एक बार फिर से बंद हो गया है। लेकिन इस बार इसके शटडाउन होने की वजह इसका अधिक पॉल्यूशन फैलाना नहीं, बल्कि बिजली कंपनियों से इसका पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) खत्म होना बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि इससे डिस्कॉम भी राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि इस प्लांट से बिजली कंपनियों को बिजली खरीदना खासा महंगा पड़ रहा था। सूत्रों का कहना है कि अब बिजली कंपनी टाटा पावर और बीएसईएस राजधानी एवं बीएसईएस यमुना ने फिलहाल राजघाट प्लांट से बिजली खरीदने से इनकार कर दिया है। इसका दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि इन दिनों तापमान में कुछ गिरावट होने की वजह से बिजली की मांग में भी कमी आई है। इस वजह से डिस्कॉम को राजघाट प्लांट से महंगी बिजली खरीदने की कोई जरूरत नहीं रह गई है।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

गंगा अभियान पर जोशी के बयान से भाजपा असहज

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य व वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी के गंगा की सफाई पर उठाए गए सवालों को लेकर भाजपा में अंदरूनी खलबली मचनी शुरू हो गई है। यह पहला मौका है जब मोदी सरकार के एक साल में पार्टी के भीतर से सरकार के किसी कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए गए हों।

हालांकि पार्टी ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। वह इसे उनके निजी विचार भर करार दे रही है। वहीं, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने दावा किया है कि दस साल में गंगा साफ हो जाएगी। गंगा सफाई पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना होने व उसके लिए सरकार की तरफ से की जा रही तैयारी पर सवाल उठना भाजपा व सरकार के लिए असहज करने वाला है।

क्या कहा था जोशी ने : जोशी ने गुरुवार को वाराणसी में कहा था कि गंगा में जहाज चलाने का हठ ठीक नहीं है। साथ ही गंगा पर प्रस्तावित बांधों का भी विरोध करते हुए कहा था कि ये बांध गंगा की प्राण-वायु सुखा देंगे। उन्होंने गंगा निर्मलीकरण अभियान को भी अधूरा करार दिया था।

उमा भारती जल्द कर सकती हैं मुलाकात : जोशी के बयान के बाद पार्टी गंभीर हो गई है। सूत्रों के अनुसार, जल संसाधन मंत्री उमा भारती व नितिन गडकरी इस मामले पर जल्दी ही जोशी से बात कर उन्हें सरकार की मंशा व काम के बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

टिहरी बांध पर मुरली मनोहर जोशी की भी थी मुहर

एक तरफ जोशी मुखर हुए तो दूसरी तरफ उनके विरोधी भी सक्रिय हो गए। उनका कहना है कि जब टिहरी बांध बन रहा था और गंगा की अविरलता बांधी जा रही थी तो डॉ. जोशी मौन क्यों रहे। उलटे उन्होंने टिहरी बांध को मंजूरी भी दी। वाजपेयी सरकार के समय गंगा पर टिहरी बांध बनाए जाने के समय उसको भूकंप आदि के मुद्दे पर एक समिति बनाई थी, जिसके प्रमुख डा जोशी थे। इस समिति की मंजूरी के बाद ही टिहरी बांध को हरी झंडी मिली थी।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

मामला तो घरेलू राजनीति का है

पत्रिका 6-6-15

स्मृति एस. पटनायक
सीनियर रिसर्च फेलो, आईडीएसए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा में तीस्ता जल पर फिलहाल कोई समझौता होने की उम्मीद नहीं है। यह यात्रा तो दोनों देशों के बीच हाल में हुए 'भूमि सीमा समझौता' के औपचारिक आदान-प्रदान और अन्य व्यापार, ट्रांजिट कनेक्टिविटी आदि मुद्दों पर ही अधिक केंद्रित रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश जा अवश्य रही हैं पर अभी तक तीस्ता जल को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तीस्ता को लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बीच बातचीत चल रही है, पर अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना शेष है। संभव है कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर आएं तो तीस्ता जल समझौते पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हो जाए।

1984 में हुए तीस्ता जल समझौते के अनुसार तीस्ता नदी के जल को भारत और बांग्लादेश के बीच बांटा जाना था। जिसके अनुसार 39 प्रतिशत जल भारत को, 36 प्रतिशत बांग्लादेश को तथा शेष 25 प्रतिशत जल के बंटवारे पर दोनों देशों के बीच समझौता होना था। पर 2011 में दोनों देशों के बीच 50-50 प्रतिशत जल बंटवारे की बात उठी। अब जो बात हो रही है वह इसी फार्मूले के आधार पर हो रही है। ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति रही है। उनका कहना है कि उत्तर बंगाल की जल जरूरतें अधिक हैं और पश्चिम बंगाल की कीमत पर बांग्लादेश के हितों की पूर्ति नहीं की जानी चाहिए। इसको देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो जाता है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तथा तृणमूल और भाजपा दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल चुनाव में होंगे। ऐसे में दोनों में कोई यह नहीं चाहेगा कि उस पर यह आरोप लगे कि उसने देश के हितों की अनदेखी की। इसलिए अभी फिलहाल तीस्ता जल पर कोई समझौता होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है।

तीस्ता जल संधि नहीं होने से बांग्लादेश में असंतोष नहीं पनपेगा। तीस्ता का जितना पानी उसे मिलता था, वह उसे मिल रहा है। उसकी मांग कुछ अधिक पानी की है। इसी पर विवाद है। हड़बड़ी में कोई समझौता होने और फिर उस कारण से देश में असंतोष या विरोधी भावना पनपने से अच्छा है कि पूर्ण सोच-विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

बंद करो चम्बल में नालों का गिरना

एनजीटी ने दिखाए तेवर, निगम और यूआईटी को दिया तगड़ा झटका

मांगी थी 6 महीने की मोहलत, दिए सिर्फ 3 महीने

पीसीबी की जांच में हुआ खुलासा, चम्बल में सीवर डालने से हुई थी मछलियों की मौत

कोटा @ पत्रिका

patrika.com/city

सीधे चम्बल में गिर रहे नालों का उत्प्रवाह रोकने के मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने नगर निगम और यूआईटी को तगड़ा झटका दिया है। दोनों संस्थानों ने नालों का प्रवाह रोकने के लिए के लिए छह महीने का वक्त मांगा था जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दलीप सिंह ने तीन महीने के अंदर सारा काम पूरा करने का आदेश सुनाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि सितंबर के बाद कोई नाला सीधे चम्बल में गिरता मिला तो आला अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय संरक्षित नदी चम्बल के अस्तित्व को बचाने के लिए एनजीटी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का छह साल बाद भी समुचित क्रियान्वयन न होने पर एनजीटी ने खासी नाराजगी जताई है। साथ ही नगर निगम और यूआईटी को तीन महीने के अंदर सभी नालों का दूषित उत्प्रवाह सीधे नदी में गिरने से रोकने का आदेश जारी किया है। हालांकि निगम और यूआईटी के अफसरों ने इसके लिए छह महीने का वक्त मांगा था, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं न्यायमूर्ति दलीप सिंह ने दोनों संस्थानों को चेतावनी भी जारी की है कि सितंबर के बाद कोई भी नाला सीधे चम्बल में गिरता मिला तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम पर तलवार

चम्बल में सैकड़ों मछलियों के मरने के मामले में नगर निगम की गर्द फंसती नजर आ रही है। मौके से लि गए पानी के नमूनों की चार दिन त चली जांच के बाद प्रदूषण नियंत्र बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बड़ी मात्रा में सीवेज डाले जा के कारण कॉलीफॉर्म की मात्रा बहु ज्यादा बढ़ने से अपस्ट्रीम अचानक ऑक्सीजन की मात्र खासी कम हो गई। इसी वजह से मछलियों का दम घुट गया औ उनकी मौत हो गई। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी राजीव पारीक ने बताया कि आरोप तय कर कार्रवा करने के लिए पीसीबी मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है।

पत्रिका-6-6-15

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (M.)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

'कावेरी का जल प्रदूषित नहीं करे कर्नाटक'

पत्रिका — 6-6-15

अनुपचारित सीवेज व औद्योगिक अपशिष्ट बहाने से रोकने की मांग

चेन्नई @ पत्रिका

patrika.com/city

तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक की कावेरी तथा इसकी सहायक नदियों में अनुपचारित सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट बहाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की।

तमिलनाडु ने याचिका में कहा है कि जीवनदायिनी कावेरी नदी की तमिलनाडु में प्रवेश के पहले की भौतिक अवस्था खतरे में है। इसकी कई सहायक नदियां एवं छोटी प्रवाहिकाएं या तो न के बराबर हैं अथवा सीवेज को बहाने वाली नहर में तब्दील हो चुकी हैं।

सीवेज तथा अवशिष्ट के अंधाधुंध प्रवाह से नदी की प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली नष्ट हो रही है। तमिलनाडु ने शीर्ष अदालत से कहा है वह कर्नाटक को निर्दिष्ट करे कि सुनियोजित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रदूषित जल को शुद्ध कर कावेरी और पेन्नायर नदियों में प्रवाहित करे।

तमिलनाडु की जीवनरेखा

याचिका में कहा गया है कि कावेरी और पेन्नायर तमिलनाडु की जीवनरेखा हैं जो कर्नाटक के नंदीदुर्ग पर्वत से निकलती हैं और राज्य में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों से उत्तरी तमिलनाडु के पांच जिलों कृष्णगिरि, धर्मपुरी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम और कडलूर में सिंचाई होती है। कावेरी का पानी फिर सेलम जिले के मेट्टूर स्थित बांध में जाता है तथा यहां वीरानम जलाशय से चेन्नई के लिए पेयजल की आपूर्ति होती है।

तमिलनाडु ने याचिका में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) दक्षिण के पेन्नायर नदी से सितम्बर 2014 से फरवरी 2015 के बीच लिए जल के नमूनों का हवाला दिया। इन नमूनों का बोर्ड की बेंगलूरु स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण हुआ।

इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन और फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित प्रमाप से काफी अधिक पाई गई। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अप्रेल महीने में इन दो नदियों से लिए सैम्पल की जांच कराई थी। इस परीक्षण में भी ये दोनों तत्व अधिक मात्रा में पाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट से याचना की गई है कि एक निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए जो न केवल इन नदियों में प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल की पड़ताल करे बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि इस तरह के जल को नदी में प्रवाहित करने से पहले पूरी तरह शुद्ध किया जाए।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के जल संसाधन व सिंचाई मंत्री शिवराज तंगडागी ने कर्नाटक विधानसभा को सूचित किया था कि हररोज 1400 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल का प्रवाह तमिलनाडु में होता है। उनके इस बयान के बाद तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की।

तमिलनाडु को देंगे कानूनी मोर्चे पर जवाब

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा कि कावेरी नदी जल प्रदूषण के बारे में तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच के समक्ष दायर की गई याचिका का कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। सिद्धरामय्या ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि तमिलनाडु सरकार यदि न्यायालय में जाती है तो हम भी न्यायालय में कानूनी संघर्ष करेंगे और कानून के जरिए ही जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ संपत्तियों के मामले में कर्नाटक के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का बदला लेने के लिए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का कदम उठाया है।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times | Nav Bharat Times (Hindi) | M.P.Chronicle
Statesman | Punjab Keshari (Hindi) | Aaj (Hindi)
The Times of India (N.D.) | The Hindu | Indian Nation
Indian Express | ✓ Rajasthan Patrika (Hindi) | Nai Duniya (Hindi)
Tribune | Deccan Chronicle | The Times of India (A)
Hindustan (Hindi) | Deccan Herald | Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC

जूनागढ़ में ओले, बारिश और अंधड़

कई जगह पेड़ गिरे, होर्डिंग्स उड़े, गुजरात में बादलों के बीच फिर बढ़ा पारा

अहमदाबाद/जूनागढ़ @ पत्रिका
patrika.com

सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले व अन्य भागों में शुक्रवार शाम को एकाएक बदले मौसम के बीच तेज हवा शुरू हो गई। इसके बाद कहीं ओले तो कहीं बारिश होने लगी। तेज हवा के कारण कई वृक्ष धराशाई हो गए तो अनेक होर्डिंग भी गिर गए। दूसरी ओर राज्य के अन्य भागों में भी बादल छाए रहे। गुरुवार की तुलना मे शुक्रवार को तापमान भी बढ़ गया।

जूनागढ़ जिले में सुबह से ही पड़ रही गर्मी के बाद शाम को एकाएक मौसम में परिवर्तन आया। इसके बाद शहर व जिले के माणवदर, वंथली तथा सासणगीर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। वंथली में ओले के साथ करीब ढाई इंच बारिश हो गई। जिससे जगह-जगह पानी भर गया। शापुर में भी दो इंच बारिश होने की खबर है। तेज हवा के कारण जूनागढ़ और वंथली में कई वृक्ष और होर्डिंग भी गिर गए। एसटी बस डिपो के निकट व नवागाम और मेंडरडा के बीच सड़क पर वृक्ष गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। दूसरी ओर मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक प्रदेश के विविध भागों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें प्रमुख रूप से सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के अलावा दीव, दमन, दादरानागर हवेली में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान में वृद्धि हुई है। शुक्रवार को सुरेन्द्रनगर में एक बार फिर तापमान 43 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच गया। जबकि अहमदाबाद और वडोदरा में पारा 42 के पार दर्ज हुआ। मौसम परिवर्तन का यह सिलसिला आगामी नौ जून तक जारी रहने की संभावना है।

मानसून में देरी

दूसरी और मौसम विभाग का कहना है कि अभी से मानसून में देरी है। हाल में जो बारिश हो रही है वह अपर एयर सर्कूलेशन का असर है। मानसून आने में अभी से दस दिन का समय लग सकता है।

डांग में मेघराजा की धुंआधार एंट्री

कई घरों के छप्पर उड़े, 30 गांवों में बिजली गुल, रास्तों पर कई वृक्ष धराशायी, सापूतारा-आहवा मार्ग बाधित

नवसारी. डांग जिले में शुक्रवार शाम वातावरण में आए अचानक बदलाव के बाद तूफानी हवाओं के साथ मेघराजा ने धुंआधार एन्ट्री की है। बारिश के कारण डांग के पूर्वी क्षेत्र में कई जगहों पर वृक्ष धराशायी हुए, वहीं सापूतारा-आहवा मार्ग पर पेड़ गिरने से रास्ता कुछ समय तक बाधित रहा था। बारिश व हवाओं के कारण कई घरों के छप्पर भी उड़ जाने से आदिवासियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। डांग जिले में पिछले दो दिनों से तेज गर्मी ने लोगों को परेशान किया था, शुक्रवार दोपहर बाद अचानक वातावरण में बदलाव देखा गया और शाम तक तूफानी हवाओं के साथ पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश ने पानी-पानी कर दिया।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald

M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

राजस्थान के लिए पिटारा खोल दूंगी

पंजाब - 6-6-15

जयपुर,(कासं): केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच लम्बे समय से चले आ रहे कालीसिंध नदी पानी विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान से बहुत प्यार है और मध्यप्रदेश से इस विवाद को लेकर वे राजस्थानी बनके ही बात करेंगी। भाखड़ा-ब्यास विवाद पर राजस्थान की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रबंधन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा मंत्री से भी बात की है। उमा भारती यहां बिड़ला आडिटोरियम में जल क्रान्ति अभियान के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि देश में पानी का असंतुलन मिटाने के लिए मेगा विजन तैयार करना होगा। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पहले 25 मई 2014 को मुझे बुलाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं। तब मैंने उनसे पूछा आप मुझे काम क्या देंगे? उन्होंने पूछा तुम्हें क्या पसंद है। मैंने कहा, मुझे गंगा चाहिए और 26 मई को मुझे जल संसाधन मंत्रालय के साथ गंगा संरक्षण विभाग का दायित्व भी सौंप दिया। उमा ने मोदी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मसीहा हैं। ऐसा असाधारण व्यक्ति हजारों सालों में पैदा होता है। इस जलक्रांति योजना को भी जन आंदोलन में तब्दील करना होगा।

जल क्रांति अभियान की शुरुआत के मौके पर शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला आडिटोरियम में लोगों को सम्बोधित करती केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और उपस्थित जनसमूह।

जल संकट [illegible] नम।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जनता के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। दिल्ली में जब वे मुझसे मिली तो उन्होंने राजस्थान में गिरते भू जल स्तर व आने वाले कल को लेकर चिंता व्यक्त की। यह कहते हुए राजे की आंखें नम हो गई। तब मैंने राजे को कहा कि आप चिंता न करें मेरा मंत्रालय राजस्थान के लिए पूरा पिटारा खोल देगा। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही इंटरलिकिंग योजना प्रगति पर है और इस योजना में राजस्थान प्राथमिकता पर है। उन्होंने वसुंधरा से जुड़े एक प्रसंग का भी उल्लेख किया। उमा ने कहा कि जब मैं भाजपा में नहीं थी तब जयपुर में मैंने वसुंधरा को आलोचना की थी लेकिन जब इसके बाद मेरा जन्मदिन आया तो राजे ने मुझे फोन कर बधाई दी। तब मैंने उनसे कहा कि यह आपका बड़प्पन है कि आपने यह बात दिल से नहीं लगाई।

[illegible]

उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब केन्द्र सरकार कोई योजना लेकर आती है तो कांग्रेसी कहते हैं यह भगवा योजना है। कांग्रेस को हर योजना भगवा लगती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनसे कोई सवाल करो तो मनमोहन कहते थे 'मैनुं क्या पता'? मोदी पहले प्रधानमंत्री जिन्हें सबकुछ पता है।

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section

Water shortage in Delhi imminent

WAZIRABAD BARRAGE Haryana restricts flow of water into the Yamuna causing water level at the barrage to fall

Neelam Pandey
neelam.pandey@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi faces an imminent water shortage crisis. Water levels at one of the biggest sources, which helps meet the Capital's requirements, has been falling for the past few days, causing panic among bureaucrats and lawmakers.

Water level at the Wazirabad barrage, on the Yamuna, has been consistently falling since May 28. Sources say that the CEO of DJB has written a letter to the principal secretary of Haryana, Irrigation and Water Resource asking him to look into the matter immediately. Delhi's chief secretary KK Sharma also wrote a letter to the chief secretary of Haryana to resolve the issue quickly.

In its letter, DJB argued that such disruption of water supply during the summer can create unrest in public and even result in law and order problem. "I would like to bring to your notice that release of water to Delhi through Yamuna river has been suddenly stopped by Haryana since May, 28, 2015 resulting in rapid decrease in the pond level at Wazirabad," states the letter.

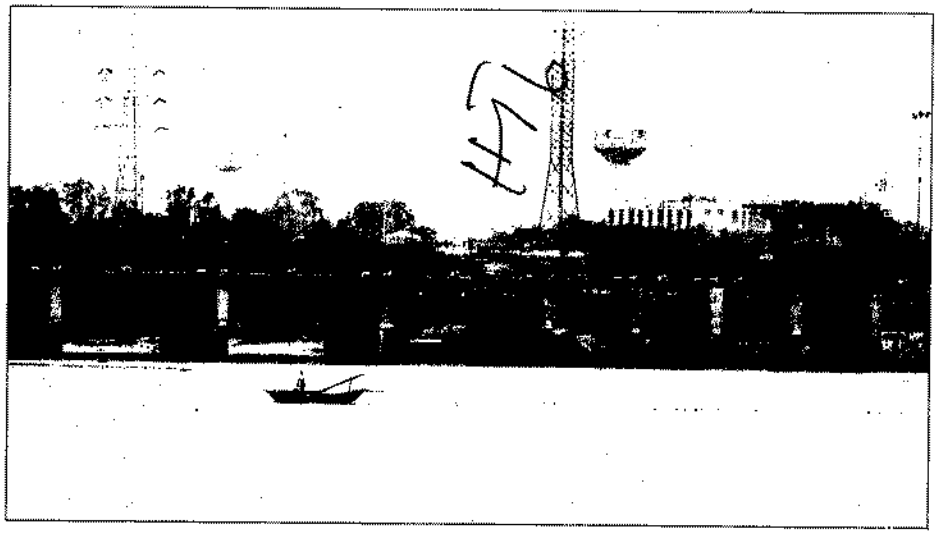

■ Haryana stopped water supply to the Yamuna on May 28, leading to a drop in water level at the Wazirabad barrage.

HT FILE

Every summer, the Capital faces shortage of water and engages in tussle with Haryana. Both the states, in turn, cite their annual requirements and claim the other is demanding beyond the stipulated supply.

The SC in its 1996-order had asked Haryana to ensure that the Delhi Jal Board's (DJB) treatment plants at Wazirahad and Haiderpur are full throughout the year so that the Capital meets its drinking water demand.

DJB uses water from the Wazirabad barrage for two water treatment plants at Wazirabad and Chandrawal respectively. Officials say water production is normal so far, but if the water-level decreases further production will be severely affected.

Water at Wazirabad has reached a level where any further decrease could lead to disruption in production. The matter might be escalated at the chief ministerial-level if it is not resolved soon. "We managed the current level of production by opening a connection between the Munak canal and the Wazirabad barrage but any further reduction water-levels could lead to a crisis," a DJB official says.

Earlier in the year Aam Aadmi Party (AAP)-led government had written to Haryana chief minister Manohar Lal Khattar, asking the latter to maintain the level of water as stipulated by the Supreme Court (SC) in 1996.

WATER WOES

- Water for the Capital is harvested and stored at the Wazirabad barrage
- The SC in 1996 ordered Delhi and Haryana to ensure that 674.5 feet water is maintained at the Wazirabad barrage
- After the SC order, Delhi asked Haryana to build a canal from Munak to divert water for Delhi's requirement
- Delhi needs 870-880 million gallons daily (MGD), with a per capita demand of 252 liters/day
- On Friday the level stood at 673 feet

BJP PROTESTS SHORTAGE OF WATER IN DELHI

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Bharatiya Janata Party (BJP) launched a protest against Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party for failing to resolve power and water crisis in the Capital.

The party launched its protest against the government of Delhi in all 14 districts of the capital.

Speaking at launch of the protest Satish Upadhyay, president of the BJP state unit in Delhi, said, "With additional water being sourced from Munak Canal, Delhi is now getting more water than in the past years from Haryana and Uttar Pradesh. Yet, residents today are facing worst possible water crisis."

The party held protests at Green Park, Preet Vihar, Rithala, Nangloi and other places. "Water is scarce and what is being supplied is unfit for drinking. Supply of free drinking water has become a of joke. Every day we receive complaints from residents across the city claiming they get water supply on alternate days. We will continue to protest till it is resolved," he added.

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times | Nav Bharat Times (Hindi) | M.P.Chronicle
Statesman | Punjab Keshari (Hindi) | A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.) | The Hindu | Indian Nation
Indian Express | Rajasthan Patrika (Hindi) | Nai Duniya (Hindi)
Tribune | Deccan Chronicle | The Times of India (A)
Hindustan (Hindi) | Deccan Herald | Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Monsoon arrives in Kerala but govt braces for drought

SHOWERS Met declares monsoon in the state after two consecutive days of rain

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The June-September monsoon swept into Kerala on Friday, bringing widespread showers and draping parts of neighbouring Tamil Nadu and southern Karnataka after a brief four-day delay, the India Meterological Department has said.

The Met declared monsoon in the southern state after two consecutive days of widespread rains of at least 2.5mm, a key condition. "The entire South Arabian Sea, Lakshwadeep, coastal Karnataka and some parts of Tamil Nadu are now covered," a Met official said.

Temperatures came down in the three southern states after a deadly heat wave that is estimated to have killed 2,000. On June 2, the weather bureau lowered its forecast of this year's rainy spell from "below-normal" earlier to "deficient", stoking fears of a drought.

Agriculture minister Radha Mohan Singh held review of emergency measures on Friday as India braces for a possible drought. The Centre has asked to make full use of the rural jobs programme MNREGA to boost farm incomes on fears of a bad harvest.

Unseasonal rains ruined winter harvests and caused farm incomes to fall 1.4% in the January and March quarter, even as the overall economy grew 7.5% in the first three months of the year.

The monsoon is vital for Asia's third-largest economy, as two-thirds of Indians depend on farm income and nearly 60% of the country's farm land does not have irrigation facilities. Poor rains tend to crimp food output, stoking inflation.

Friday's meeting was attended by secretaries and officials from the agriculture, Indian Council of Agricultural Research, power, and water and rural development ministries, among others.

Nearly 116,000 water-harvesting and drought-related projects are already under way as part of drought preparedness, the farm minister said. The power ministry has made provisions for greater energy demand in rural areas, while 90 lakh tone fertilizers have been dispatched to states, against 60 lakh tonne requirment, Singh added.

Temperatures came down in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka after the rains. REUTERS

MONSOON DATE

Delhi: June 29
Mumbai: **June 10**
Kolkata: **June 10**
Guwahati: **June 5**
Patna: **June 15**
Entire country: by **July 15**

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

✓ Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

We must see both the woods and the trees

Policies must be holistic and recognise the interconnectedness between the environment and development

Hemendra Kothari

It's an exciting time to be an Indian — our country is poised on the edge of accelerated economic growth. But this is not possible without a stable environment. It is essential, therefore, that we focus on protecting our natural infrastructure, which forms the bedrock of our economy.

The flow of benefits from our ecosystem is immense — it supplies clean air, water and climate security. Globally, 200-300 million people depend directly, or indirectly, on forests for food. Some studies suggest that ecosystem goods and services account for over half the 'gross domestic product of the poor'. This is particularly significant for India where 200 million people live in and around forests, relying heavily on these ecosystems for their daily survival. More than 600 indian rivers either originate from, or are fed by, tiger landscapes and these habitats supply water to cities hundreds of kilometres away. The Corbett Tiger Reserve, for instance, forms the catchment area of the Ramganga reservoir that provides 190 million cubic metres of drinking water to New Delhi. In Maharashtra, Nagpur is dependent on lhe Pench Lake, harboured in the Pench Tiger Reserve, for its water supply. The economic repercussions of neglecting the environment are severe.

■ In rural areas, women walk several hours every day to get water for their families REUTERS

The rights of women and children, too, are inextricably linked to environmental issues. in rural areas, women walk several hours every day to get water for their families. As wells dry up, girls are more likely to be pulled out of school to help their mothers with collecting water. The World Bank estimates that 21% of communicable diseases in India can be linked to unsafe water with diarrhoea causing more than 1,600 deaths every single day.

This begs the question — what should India do? As with all effective solutions, the answer is simple to give but difficult to implement. We need to start at the very source of our policy-making, designing laws and programmes that are holistic and recognise the interconnectedness between the environment and development. This needs to percolate to the ground level particularly in landscapes where communities and wildlife live in close proximity. The key lies in finding solutions that allow communities access to the same benefits as you and me, while safeguarding the precious natural resources they live alongside. Environmental impacts and appropriate mitigation measures need to be inbuilt in projects, not tacked on as an afterthought to secure a clearance from the ministry of environment and forests.

The challenges lying ahead for India are not easy but there is immense potential to transform them into opportunities. We must involve forest departments, local communities and other stakeholders to find solutions that benefit both people and wildlife. It is a long road but one which we must travel together with all stakeholders.

Hemendra Kothari is founder and chairman of the Wildlife Conservation Trust
The views expressed are personal

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Will it be Teesta's turn next?

S K Sarkar

Prime Minister Narendra Modi's visit to Bangladesh raises a hope for a step forward in the resolution of the long-pending Teesta water-sharing issue with Bangladesh.

Since 1972 Bangladesh has wanted a 50 per cent share of Teesta river water. Teesta is one of the 54 rivers on the India-Bangladesh border. Of these there already is a water-sharing agreement on the Ganga river. The sharing of water on other important rivers such as Teesta, Dharla, Dudhkumar in West Bengal and Feni, Manu, Muhuri, Khowei, Gumti in Tripura, have been under discussion for quite some time.

Teesta river originates in Sikkim, flows through Jalpaiguri town in West Bengal and finally joins Brahmaputra river at Teestamukh, Bangladesh. It has over 12,000 sq km drainage area of which 89 per cent lies in Indian territory. In Sikkim there are mostly hydroelectric projects, thus there is no consumptive use of water, and no effect on monsoon flows. West Bengal has constructed a Teesta Barrage, 90 km upstream of the Indo-Bangladesh border at Gajoldoba in Jalpaiguri, while Bangladesh has constructed the Doani/Dalia barrage downstream, 15 km from the international border. The shortage of water for irrigation occurs between November and April.

The two countries reached an understanding in July 1983 for an ad hoc sharing of Teesta water flows during the dry season: an allocation of 36 per cent for Bangladesh, 39 per cent for India and 25 per cent remaining unallocated. This arrangement helped Bangladesh in getting finance for the Dalia barrage construction.

Past discussions between the two countries for reaching an agreement on the interim sharing of Teesta water for 15 years were on the following lines: a) during lean season, Teesta water flow be measured jointly at three locations i.e. Indian barrage at Gajoldoba, at Bangladesh barrage at Dalia and downstream at Kunia, Bangladesh; 2) after collection of data, the 90 per cent dependable flow data in Teesta river be worked out; 3) after deduction of environmental flow and 450 cusec for its use, India to release water at Gajoldoba barrage in such a way that 50 per cent of the water available at Gajoldoba be available at Dalia barrage in Bangladesh. This arrangement was thought to be a feasible proposition because of geological conditions, which cause about 25 per cent water regeneration between Gajoldoba Barrage and Dalia barrage. This meant that West Bengal government would have to release only 25 per cent of the water available at Gajoldoba, which when added to 25 per cent regeneration, would result in receipt of water by Bangladesh equivalent to 50 per cent of the water available at Gajoldoba.

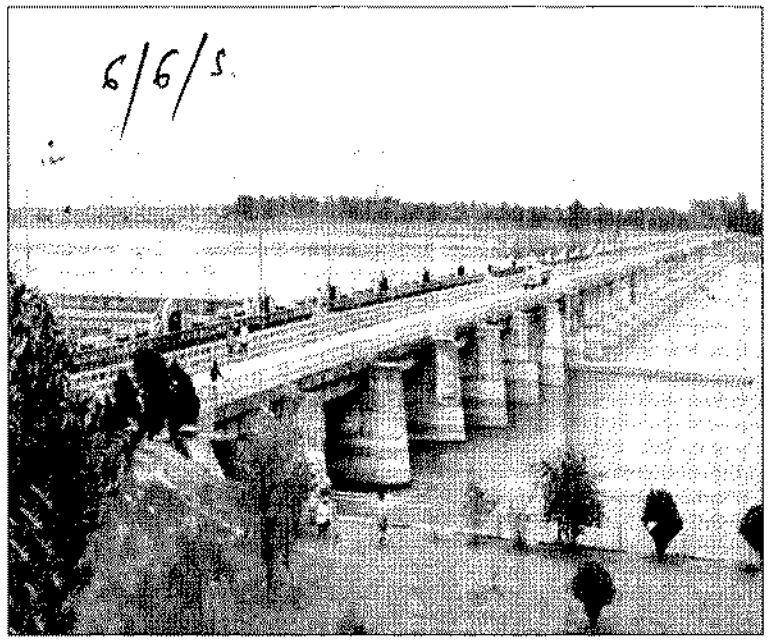

Unfortunately, government of West Bengal is agreeable to share only 25 per cent of available water at Gajoldoba plus the river flow (about 8 per cent). To them, the proposition on the manner of release as stipulated in the earlier paragraph is vague, as there could be years when regeneration of water between Gajoldoba and Dalia may not be 25 per cent. In that situation, committing half the water available at Gajoldoba may affect the important Teesta Barrage project. This project is significant, being the largest irrigation project in the eastern region, involving irrigation potential of 9.22 lakh hectare and 67.5 MW of hydropower.

In any international water course issue, there is a need for resolution by adopting equitable, non-discriminatory guiding principles for sharing of water resources, say as per those available in the UN Water Course Convention, 1987. It urges all riparian States to cooperate on the basis of sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit and good faith in order to attain optimal utilisation of an international water course. Interestingly, India, Bangladesh and China did not ratify this Convention. In resolving the Teesta river water sharing problem, the basic principle should be on these lines.

For the last few years, Bangladesh has raised the issue of less availability of Teesta water due to non-release by India from its barrage at Gajoldoba in the lean season. The West Bengal government claims less water is available than it needs, hence the shortfall. The controversy continues.

Within the country there has to be a political consensus for any solution. In addition, the hard data on the ground should show that India (especially West Bengal) will not be a loser with the interim Teesta river water sharing arrangement, especially assuring its non-detrimental impact on the Teesta Barrage project. Both the countries should work together in gathering and analysing technical data. The first move must come from the government of India to convince the state governments (s) about the efficacy of a mutually beneficial solution. There i hope, now that the Land Borde Agreement with Bangladesh is reality.

THE WRITER IS DISTINGUISHED FELLOW, TERI AND FORMER SECRETARY, MINISTRY OF WATER RESOURCES, GOVERNMENT OF INDIA

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Climate change, terror on G-7 agenda

PRESS TRUST OF INDIA
Washington, 5 June

Climate change, including role of India and China, global economy and counter-terrorism tactics will be some of the key topics that will dominate the upcoming G-7 summit in Germany, senior US officials said.

The G-7 is a grouping of top seven industrialised countries of the world -- Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan and the US.

Russia which was added into the group in 1998 was suspended last year after Moscow annexed Crimea.

The June 7-8 Summit of G-7 leaders in Bavaria would be held without Russia.

US President Barack Obama would be leading the American delegation to the Summit wherein according to his close aides he would press for more sanctions on Russia for its alleged interference in Ukraine.

"We will affirm the importance of maintaining sanctions on Russia to incentivize full implementation of the Minsk agreement, and also to serve as a deterrent against further Russian aggression," said Ben Rhodes, the Deputy National Security Advisor.

"It's very important coming out of these G-7 meetings that the world is seen as speaking with one voice in support of those important consequences that have been imposed on Russia, and to demonstrate that Russia will continue to face those sanctions until a diplomatic solution is fully implemented," he said.

Leaders of G-7 countries would also be discussing the proposed nuclear agreement with Iran and the progress in the anti-ISIS coalition in Syria and Iraq, he said.

Meeting ahead of the Paris Summit later this year, the leaders of the top industrialised countries would also devote quite amount of time of their discussion on climate change, he said.

"We have been working -- obviously the President's climate agenda was released; the Climate Action Plan was released two years ago. We continue to work domestically," said Caroline Atkinson, deputy national security advisor on international economics.

"We also have been engaged very closely with major emerging economies -- notably China, also India -- to make sure that they are going to work with us for a successful Paris agreement," she said.

"We see the G-7 as an important milestone on this issue, and one where we will be able to speak both with other G-7 countries about ways that we can move both with announcing our own targets and taking steps to support other countries and to protect the environment," she said.

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Monsoon worries, real or not

By downgrading the monsoon forecast for the year to 'deficient', the India Meteorological Department has pressed the panic button. The forecast now talks of 88 per cent of the long-period average, down from the preliminary figure of 93 per cent. The revised estimate is indeed cause for concern, as it holds the possibility of the country being pushed into a drought situation. These are forward-looking numbers no doubt. Yet the signals can hardly be ignored. Finance Minister Arun Jaitley has sought to talk up the sentiment by suggesting that the fears are exaggerated, and he may well be right. In his view, the geographical distribution of rainfall and its timing will matter more than the total volume of precipitation. Yet, policy-planners at the fiscal and monetary levels have not shied away from articulating their anxiety. The Centre has said it is ready to face a deficit monsoon. Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh has made it clear that the situation is being monitored on a daily basis and that a 'contingency plan' is in place. The immediate worry, nay task, is to quickly devise an emergency plan to tackle the social and economic consequences of a possible drought. In the near-term, the government may do well to prepare a ready-to-roll out action programme to provide farmers a support system and fallback mechanism to ensure that they aren't consumed by the severity of the impact, should there be a drought. This could well prove to be one of the toughest tests yet for the year-old Narendra Modi government. To minimise the annual concerns on this front, governments at the Centre and the States will have to go beyond mere mitigation strategies and work out a long-term irrigation plan in an integrated and holistic manner to optimise the groundwater potential as well.

If the forecast does come true, however, India could be facing the 12th worst drought since 1950. Already hit by unseasonal rain during the *rabi* season, this portends further trouble during the *kharif* cycle. This could lead to serious problems on the food front with consequences on the price situation. Already, lack of rural demand is dragging the economy down. The inflation-focussed Reserve Bank of India will have no more leeway to cut the interest rate in such a situation. Three quick rate cuts by the RBI totalling 75 basis points this year have not really seen any major reduction in lending rates by banks at the ground level. With mounting stressed assets and poor credit off-take, the banking industry has so far chosen to be a reluctant actor in the play. The missing X-Factor has conspired with the existing shortfalls in capacity utilisation to make the industry look forlorn. The situation demands proactive action.

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Ganga can't be cleaned in 50 years: Joshi

VARANASI: Toeing a line different from his party-led government on ambitious *'Namami Gange'* programme, senior BJP leader Murali Manohar Joshi on Friday said that the Ganga can't be cleaned even in next 50 years the way the project to clean the river was being carried out.

Expressing his reservations on clean Ganga project, Dr. Joshi said cleaning the Ganga would be a far-fetched dream till there was uninterrupted water flow in the river.

"Cleaning the Ganga would be a far fetched dream till there was an uninterrupted flow of water in the river. The river cannot be cleaned even in next 50 years, they way river was being cleaned by dividing it into small parts, converting it into small ponds," Dr. Joshi said, adding that the Ganga was our lifeline, and any threat to the Ganga was a threat to our culture and tradition.

The senior BJP leader advocated for an uninterrupted flow of water in the Ganga and questioned Union Minister Nitin Gadkari's Inland waterways project of running cruises and large ships in the Ganga for transportation of heavy goods.

"How will you run large ships when big boats are unable to move on the river *(Ganga mein Jahaz chalana to door, badi nav bhi nahi chal payengi, is yojana ko lagu karne se pahle Ganga ki maujuda isthti ki jaanch karale)*."

Uma Bharti's reaction

Meanwhile in Jaipur, Union Water Resources Minister Uma Bharti on Friday said she would seek Murli Manohar Joshi's views to remove shortcomings in the *'Namami Gange'* programme after he questioned the project and said that it would not be be completed within two years. - PTI

News item/letter/article/editorial published on 6/6/15 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Poor rain may not hit grain output

Data point to only minor effect on production

TCA Sharad Raghavan

NEW DELHI: A deficient monsoon does not necessarily affect India's foodgrain production severely. Since 1976, rainfall dropped by more than 10 per cent over the previous year nine times. However, only in two of these years, food production fell by a corresponding percentage. In the remaining seven, the fall was minor, an analysis by *The Hindu* shows.

The finding is in line with Union Finance Minister Arun Jaitley's statement on Thursday that foodgrain production would not be affected in the event of deficient rainfall this year.

NOT ALL GLOOMY

9 Number of times rainfall has dropped by **10 %** or more **since 1976**

2 Of these, only two years saw **food production falling by as much**

- This year **is a rarity** as it'd be the second consecutive year of poor rainfall
- Analysis shows **food management** will be more of a problem than production

This year, however, is a rarity — if the forecast of the India Meteorological Department of deficient rainfall holds, then this would be the second consecutive year to experience the shortfall.

"There could be a cause for worry ... The effect on agriculture of deficient rainfall two years in a row is much more disastrous — the detrimental effect can be more than double the effect of a single year of deficient rainfall," former Planning Commission Member and economist Abhijit Sen told *The Hindu*.

Mr. Sen pointed out that the last time India had two consecutive years of deficient rainfall in 1986 and 1987, food production did decline, but it bounced back sharply owing to surplus rains in 1988.

Data for the previous incidence of back-to-back rainfall deficient years, 1904-05 and 1965-66, were not available.

Mr. Sen said that since this was the first time the IMD had predicted a drought, it was a very strong signal that should not be played down.